

99 MAY 2007

बिजली की चोरी कैंसर के समान : मनमोहन

नई दिल्ली, (आईएनएस, एजेंसियां): बिजली चोरी के खिलाफ सशक्त अभियान का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज यहां कहा कि बिजली उत्पादकता में बढ़ौतरी का प्रयास अभी भी पूरा रंग नहीं ला रहा है वहीं बिजली चोरी से आर्थिक प्रगति बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

उन्होंने विद्युत क्षेत्र पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली चोरी विद्युत क्षेत्र के लिए कैंसर के समान है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाना होगा, क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, विद्युत मंत्री सुशील कुमार शिंदे और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे ईमानदार उपभोक्ता, जो नियमित रूप से बिजली का बिल अदा ▶ शेष पृष्ठ 2 पर ॥

बिजली की चोरी...

करते रहे हैं, उन्हें बिजली चोरी से चपत लग रही है। उन्हें बिजली चोरी से होने वाले नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई कि भारत को अभी भी बिजली संकट से रूबरू होना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई कि भारत को औसतन करीब 10 फीसदी बिजली किल्लत और पीक आवर में 13 फीसदी से अधिक बिजली की किल्लत झेलनी पड़ती है। कई राज्यों में तो बिजली किल्लत की दर 25 फीसदी तक है। उन्होंने कहा कि बिजली की यह घोर किल्लत हमारी आर्थिक गतिविधियों को ब्रेक लगा सकती है। हम विद्युत क्षेत्र में उच्च उत्पादकता के लक्ष्य को पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। हमें इस दिशा में निर्णायक सफलता अर्जित करनी होगी।

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें चरणबद्ध तरीके से विद्युत प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें। हमारे लिए वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। उन्होंने दसवीं योजना में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ौतरी के लक्ष्य का



नई दिल्ली में सोमवार को विज्ञान भवन में ऊर्जा मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हाथ मिलाने के बाद आगे बढ़ते हुए। (छाया : प्रैट.)

50 प्रतिशत ही हासिल हो पाने पर गहरी चिंता जताते हुये कहा कि यह केंद्र और राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की खामियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय कम है तथा 2012 तक बिजली की किल्लत को पूरी तरह दूर करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु युद्धस्तर पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें परियोजना प्रबंधन और निरारानी के लिए विशेष उपाय करने होंगे ताकि बिजली परियोजनाएं समय पर पूरी हों।